



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052020-219460
CG-DL-E-20052020-219460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2020/वैशाख 30, 1942

No. 126]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2020/VAISAKHA 30, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2020

मामला सं. एडीडी-एसएसआर-10/2020

विषय : चीन जन.गण. तथा रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “रबड़ के अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक” के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/15/2020-डीजीटीआर.—1. मै. कार्बन ब्लैक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीबीएमए) (इसके पश्चात आवेदक के रूप में संदर्भित) ने चीन जन.गण. तथा रूस (इसके पश्चात संबद्ध देशों के रूप में संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “रबड़ के अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक” (इसके पश्चात “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” अथवा “संबद्ध वस्तु” के रूप में संदर्भित) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात “नियमावली” के रूप में संदर्भित) के अनुसार घरेलू उत्पादकों अर्थात् फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड; हिमाद्री स्पेशलिटी कैमिकल्स लिमिटेड, कॉन्टीनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड और बिरला कार्बन इंडिया प्रा. लि. की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। घरेलू उत्पादकों अर्थात् फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड; हिमाद्री स्पेशलिटी कैमिकल्स लिमिटेड और कॉन्टीनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड (इसके पश्चात “भाग लेने वाली कंपनियों” के रूप में संदर्भित) ने इस आवेदन में निर्धारित सूचना उपलब्ध कराई है।

2. आवेदक ने संबद्ध देशों के मूल के और वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया है तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा से वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने और उसे जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. आस्ट्रेलिया, चीन जन.गण, ईरान, मलेशिया, रूस तथा थाइलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच की शुरुआत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना सं. 14/21/2008-डीजीएडी के माध्यम से की गई थी। अनंतिम पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश आस्ट्रेलिया, चीन जन.गण. रूस और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर दिनांक 25 मई, 2009 की अधिसूचना सं. 14/21/2008-डीजीएडी के माध्यम से की गई थी और उस पर दिनांक 30 जुलाई, 2009 की अधिसूचना सं. 83/2009-सीमाशुल्क के माध्यम से शुल्क लगाया गया था। तत्पश्चात निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश दिनांक 24 दिसंबर, 2009 की अधिसूचना सं. 14/21/2008-डीजीएडी के माध्यम से की गई थी और उसे दिनांक 28 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 6/2010-सीमाशुल्क के माध्यम से लगाया गया था।
4. प्राधिकारी ने आस्ट्रेलिया, चीन जन.गण, रूस तथा थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) जांच की शुरुआत दिनांक 30 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 15/41/2010-डीजीएडी के माध्यम से की अथवा दिनांक 28 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 15/41/2010-डीजीएडी के माध्यम से सतत रूप से पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने की सिफारिश की और जिसे दिनांक 26 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 9/2013- सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था।
5. निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जांच की शुरुआत चीन जन.गण., रूस और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में दिनांक 15 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. 15/8/2014-डीजीएडी के माध्यम से की गई थी और पाटनरोधी शुल्कों का समय विस्तार किए जाने की सिफारिश चीन जन.गण. और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 15/8/2014-डीजीएडी के माध्यम से की गई थी और उसे दिनांक 18 नवंबर, 2015 की अधिसूचना सं. 54/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 17 नवंबर, 2020 तक वैध है।

विचाराधीन उत्पाद

6. वर्तमान एसएसआर आवेदन में विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे मूल जांच में परिभाषित किया गया है और तद्वर्तर निर्णायक समीक्षा जांच अर्थात् “रबड़ के अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक” है। पूर्व में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच और प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसार, इस उत्पाद को नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया है :

“5. विचाराधीन उत्पाद रबड़ के अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक” है। यह एक इन आर्गेनिक कैमिकल है जिसका उपयोग सुदृढ़ करने वाली फिलर के रूप में रबड़ के उत्पादन/प्रसंस्करण (टायरों सहित) में किया जाता है। कार्बन ब्लैक को एसीटीटेलीन ब्लैक, चैनल ब्लैक, फर्नेस ब्लैक, लैंपब्लैक, लैंपब्लैक, थर्मल ब्लैक और नाइर डी कार्बन के रूप में भी जाना जाता है। कार्बन ब्लैक को दो श्रेणियों – रबड़ और बिना रबड़ वाले अनुप्रयोगों को कार्बन ब्लैक में विभाजित किया जा सकता है। रबड़ के अनुप्रयोगों के लिए कार्बन ब्लैक वह कार्बन ब्लैक है, जिसका उपयोग सुदृढ़ करने वाले फिलर के रूप में रबड़ के उत्पादन/प्रसंस्करण (टायरों सहित) में किया जाता है। वर्तमान जांच रबड़ के अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के संबंध में है। बिना रबड़ के अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक जैसे कॉपीयर में इंक और कंप्यूटर प्रिंटर काट्रेज, पेंट, क्रेयन्स और पॉलिश, वर्तमान जांच के विषय क्षेत्र में नहीं आते हैं।

6. संबद्ध वस्तु उप शीर्षक सं. 28030010 के अंतर्गत इस अधिनियम के अध्याय 28 के अधीन आता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के विषय क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”

7. चूंकि वर्तमान जांच एक अंतिम समीक्षा जांच है अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जो पूर्व में की गई जांच में था। संबद्ध वस्तु उप शीर्षक सं. 28030010 के अंतर्गत सीमाप्रशुल्क के अध्याय 28 के अंतर्गत आता है। हालांकि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के विषय क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जिसे भारत में पाटित किया जा रहा है, भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। पाटित आयातों के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यो अथवा अंतिम उपयोगों में तथा घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों का तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत इन्हें “समान वस्तु” के रूप में माना जाना चाहिए। इस कारण से, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध वस्तुओं का “समान वस्तु” के रूप में माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

9. यह आवेदन घरेलू उत्पादकों अर्थात् फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड; हिमाद्री स्पेशलिटी कैमिकल्स लिमिटेड, कॉन्टीनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड और बिरला कार्बन इंडिया प्रा. लि. की ओर से मै. कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीबीएमए) द्वारा दायर किया गया है। भाग लेने वाली कंपनियों अर्थात् फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड; हिमाद्री स्पेशलिटी कैमिकल्स लिमिटेड, कॉन्टीनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड ने आवेदन में निर्धारित सूचना उपलब्ध कराई है।
10. भाग लेने वाली इन कंपनियों ने दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही उनका संबंध संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से है। भाग लेने वाली कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन में बहुत बड़ा हिस्सा होता है और भाग लेने वाली इन कंपनियों ने संगत क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है।
11. उपर्युक्त को देखते हुए तथा अपेक्षित जांच के पश्चात, प्राधिकारी यह मानते हैं कि भाग लेने वाली कंपनियां नियम 2(ख) के संबंध में पात्र घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के संबंध में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

पाटन के जारी रहने और उसके फिर से होने की संभावना

क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के संबंध में किया जाना चाहिए। आवेदक ने इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-8(2) का उदाहरण दिया है और यह उल्लेख किया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निदेश दिया जाना चाहिए कि इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के संबंध में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। उपर्युक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की कीमतें अथवा संरचित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देशों को इस तरह के तीसरे देश से इन कीमतों को आवेदक द्वारा न तो उपलब्ध कराया गया है और न ही यह सूचना किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। इसे देखते हुए, सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित भारत में भुगतान की गई कीमत अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर किया गया है जिसे बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभों के लिए योग के पश्चात भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है।

ख. रूस के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने दावा किया है कि रूस में इस उत्पाद की वास्तविक बिक्री कीमत अथवा उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि तीसरे देश को निर्यात कीमत को शामिल उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की लागतों और कीमतों में अत्यधिक अंतरों को देखते हुए नहीं अपनाया जा सकता है। रूस के सामान्य मूल्य को संबद्ध बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ के साथ-साथ रूस में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर तय किया गया है।

ग. निर्यात कीमत

14. संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तुओं के वास्ते निर्यात कीमत की गणना वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के लेनदेनवार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़ा खर्च, पत्तन खर्च, बैंक प्रभार और मूल्यवर्धित कर (चीन जन.गण. के लिए ही) के वास्ते समायोजन किए गए हैं। आवेदक द्वारा दावा किए गए निवल निर्यात कीमतों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

घ. पाटन मार्जिन

15. उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन का निर्धारण इस अधिनियम की धारा 9 क(1)(क) के अनुसार किया गया है। इस बात का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात कीमत की तुलना में अधिक है जो प्रथम दृष्टया इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि संबद्ध वस्तुओं को भारतीय बाजार में संबद्ध देशों के निर्यातकों के द्वारा पाटित किया जा रहा है।

क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना

16. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन पहले से ही कमजोर है क्योंकि उत्पादन, क्षमता की उपयेगिता, बिक्री की मात्रा, माल भंडार, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय प्रस्तावित जांच की अवधि में और खराब हो गई है। इसके अलावा, आवेदकों ने पाटनरोधी शुल्क की समाप्तिकी स्थितिमें क्षतिकी संभावना का दावा किया है और उल्लेखनीय अतिरिक्त भंडार तथा उपयोग न की गई क्षमताओं, निर्यातोन्मुखीकरण, संबद्ध देशों में उत्पादकों की क्षमता का कम उपयोग के साथ-साथ संबद्ध देशों से आयातों के द्वारा कीमत में कटौती तथा संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा उसके आगे विस्तार के संबंध में सूचना के साथ-साथ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के फलस्वरूप क्षतिके जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

17. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर और पाटन एवं क्षतिके जारी रहने/उसके फिर से होने की संभावना की पुष्टि करते हुए प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर अपने आप को संतुष्ट करते हुए तथा इस नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क (5)के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा इस तथ्य की जांच करने के लिए संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को सतत रूप से लगाए रखने के लिए आवश्यकता की समीक्षा करने हेतु निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षतिके जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।

संबद्ध देश

18. इस जांच के उद्देश्य से, संबद्ध देश चीन जन.गण. तथा रूस हैं।

जांच की अवधि

19. आवेदक ने 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (9 महीने) की अवधि के लिए जानकारी प्रदान की है और 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक जांच की अवधि प्रस्तावित की है। क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 और जांच की अवधि का प्रस्ताव किया गया है।

20. नियम २२ के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि:-

“इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, जांच की अवधि, (i) जांच शुरू होने की तारीख तक छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होगी। (ii) बारह महीने की अवधि के लिए हो और नामित प्राधिकारी को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए न्यूनतम छह महीने या अधिकतम अठारह महीने पर विचार कर सकते हैं।”

21. नियमों में उपरोक्त प्रावधान को देखते हुए, वर्तमान जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 महीने) की है तथा क्षति अवधि में 1 अप्रैल 2016- 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 – 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 -31 मार्च 2019, और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

22. इस समीक्षा जांच में दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 15/8/2014 -डी जी ए डी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे जिसमें चीन जन. गण. और रूस से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का समय विस्तार किए जाने की सिफारिश की गई है। प्राधिकारी पाटन और क्षतिकी संभावना का विश्लेषण भी करेंगे।
23. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा में लागू रहेंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

24. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सभी पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के द्वारा ई-मेल पते adg13-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर भेजे जाने चाहिए।
25. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तुओं के संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और तरीके से संबंधित सभी सूचना प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।
26. अन्य कोई भी हितबद्ध पक्षकार जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप में और तरीके से भी कर सकते हैं।
27. प्राधिकारी के समक्ष किसी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे अन्य पक्षकारों को उस अनुरोध का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।

समय-सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के द्वारा ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in दी जानी चाहिए ताकि वह नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचना दें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे इस नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में जारी किए गए व्यापार नोटिसों के संबंध में उसका एक अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का पालन नहीं करने पर प्रत्युत्तर/अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।
31. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि वे पृथक् रूप से गोपनीय और अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करें।
32. “गोपनीय अथवा अगोपनीय” अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप में स्पष्ट से चिह्नित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्ह के बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उन अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
33. गोपनीय पाठ में वे सभी सूचना निहित होंगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/अथवा अन्य प्रकार की सूचना है जो इस प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति गोपनीय के रूप में दावा करते हैं। उस सूचना के लिए, जिसके संबंध में गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना देने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।
34. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा कवर किया (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सारांश किए जाने के साथ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति हो। अगोपनीय सारांश विस्तृत व्यौरों के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है।
35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला व्यक्ति इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
36. उसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिए बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
37. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। सार्वजनिक फाइल को इलैक्ट्रॉनिक मोड में बनाए रखने के तौर-तरीकों को तय किया जा रहा है।

असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2020

Case No. ADD-SSR-10/2020

Subject : Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of “Carbon Black used in Rubber Applications” originating in or exported from China PR and Russia.

F. No. 7/15/2020-DGTR.—1. M/s Carbon Black Manufacturers Association (CBMA) (hereinafter referred to “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic producers namely, Phillips Carbon Black Limited; Himadri Speciality Chemicals Limited, Continental Carbon India Limited and Birla Carbon India Private Limited, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “ Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Rules”), for sunset review of Anti-Dumping duty imposed on imports of Carbon Black used in Rubber applications (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR and Russia (hereinafter referred to as the “subject countries”). The domestic producers namely, Phillips Carbon Black Limited; Himadri Speciality Chemicals Limited and Continental Carbon India Limited (hereinafter referred to as “Participating Companies”) have provided the prescribed information in the Application.

2. The Applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and has requested for sunset review, and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from Australia, China PR, Iran, Malaysia, Russia and Thailand was initiated by the Authority *vide* Notification No. 14/21/2008-DGAD dated 26th December, 2008. The provisional anti-dumping duties were recommended *vide* Notification No.14/21/2008-DGAD dated 25th May, 2009 on subject goods, originating in or exported from Australia, China PR, Russia and Thailand, and the same were imposed *vide* Notification No. 83/2009-Customs dated 30th July, 2009. Thereafter, definitive anti-dumping duties were recommended *vide* Notification No.14/21/2008-DGAD dated 24th December, 2009 and the same were imposed *vide* Notification No. 6/2010-Customs dated 28th January, 2010.
4. The Authority initiated a mid-term review (MTR) investigation on subject goods, originating in or exported from Australia, China PR, Russia and Thailand *vide* Notification No.15/41/2010-DGAD dated 30th August, 2011 and recommended continued imposition of the anti-dumping duties *vide* Notification No.15/41/2010-DGAD dated 28th February, 2013 which were imposed *vide* Notification No. 9/2013-Customs (ADD) dated 26th April, 2013.

5. A Sunset Review (SSR) investigation was initiated *vide* Notification No. 15/8/2014-DGAD dated 15th July, 2014 in respect of the subject goods, originating in or exported from the China PR, Russia and Thailand, and the extension of anti-dumping duties was recommended *vide* Notification No. 15/8/2014-DGAD dated 1st October, 2015 in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR and Russia, and the same were imposed *vide* Notification No. 54/2015-Customs (ADD) dated 18th November, 2015. The current anti-dumping duties are valid up to 17th November, 2020.

Product Under Consideration

6. The product under consideration in the present SSR application is same as defined in the original investigation, and subsequent sunset review investigation. i.e. 'Carbon Black used in rubber applications'. As per the original investigation & first Sunset review investigation carried out by the Designated Authority earlier, the product has been defined as under:

"5. The product under consideration is 'Carbon Black used in rubber applications'. It is an inorganic chemical used in production/ processing of rubber (including tyres), as reinforcing filler. Carbon Black is also known as acetylene black, channel black, furnace black, lamp black, lampblack, thermal black, and noir de carbone. Carbon black can be divided into two categories – rubber and non-rubber applications Carbon black. Carbon black for rubber applications is the Carbon black that is used in production/ processing of rubber (including tyres), as a reinforcing filler. The present investigation is in respect of Carbon black used in rubber applications. Carbon black used in non-rubber applications, such as inks in copiers and computer printer cartridges, paints, crayons and polishes, is not within the scope of the present investigation.

6. The subject goods fall under Chapter 28 of the Act under subheading No. 28030010. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation."

7. The present investigation being a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as in the previously conducted investigation. The subject goods fall under Chapter 28 of the Customs Tariff under Subheading No. 28030010. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

8. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the participating companies. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the participating companies. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the participating companies in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry

9. The application has been filed by M/s Carbon Black Manufacturers Association (CBMA) on behalf of domestic producers namely, Phillips Carbon Black Limited; Himadri Speciality Chemicals Limited, Continental Carbon India Limited and Birla Carbon India Private Limited. The participating companies namely, Phillips Carbon Black Limited, Himadri Speciality Chemicals Limited, and Continental Carbon India Limited have provided the prescribed information in the Application.
10. These participating companies have claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or an importer of the product under consideration in India. The production of the participating companies constitutes a major proportion in Indian production, and these participating companies have provided relevant injury information.

11. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the participating companies constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules supra.

Likelihood of continuation or recurrence of dumping

a. Normal Value for China PR

12. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The Applicant has claimed that for China, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The prices or constructed value of the product under consideration in the appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant nor is this information available with the Authority from any public source. In view of the same, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

b. Normal Value for Russia

13. The Applicant has claimed that information on actual selling price of the product, or cost of production in Russia is not publicly available. Applicant has also stated that export price to third country cannot be adopted in view of significant differences in costs and prices of different types of the product involved. The normal value for Russia has, therefore, been constructed on the basis of best estimates of cost of production in Russia alongwith associated selling, general and administrative expenses, and reasonable profit.

c. Export Price

14. The export price for subject goods for the subject countries has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges, and VAT (for China PR only). There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the Applicant.

d. Dumping margin

15. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Act. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Likelihood of continuation or recurrence of Injury

16. The Applicant has claimed that the performance of the domestic industry is already fragile as production, capacity utilization, sales volume, inventories, profit, cash profits and return on investment have deteriorated in the proposed POI. Further, the Applicant has claimed likelihood of injury in the event of cessation of anti-dumping duty, and furnished evidence with regard to significant surplus, and unutilized capacities, export orientation, low capacity utilization of the producers in the subject countries, along with information on price undercutting by imports from subject countries, and further expansions by producers in the subject countries. The Applicant has claimed that the cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of injury.

Initiation of Sunset Review

17. On the basis of the duly substantiated application of the Applicant, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of

the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from subject countries to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Subject Countries

18. For the purpose of the investigation, the subject countries are China PR and Russia.

Period of investigation

19. The Applicant has provided information for the period 1st April, 2019 to 31st December, 2019 (9 Months) and has proposed period of investigation as 1st April, 2019 to 31st December, 2019. The injury investigation period has been proposed to cover the periods 1st April, 2016- 31st March, 2017; 1st April, 2017- 31st March, 2018; 1st April, 2018- 31st March, 2019, and the POI.
20. Explanation to Rule 22 of the Rules states that:

“For the purposes of these rules, the period of investigation shall, - (i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation. (ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.”

21. In view of the above provision in the Rules, the period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st April, 2019 to 31st March, 2020 (12 months) and the injury period will cover the periods 1st April, 2016- 31st March, 2017; 1st April, 2017- 31st March, 2018; 1st April, 2018- 31st March, 2019, and the POI.

Procedure

22. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 15/8/2014-DGAD dated 1st October, 2015 recommending extension of anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR and Russia. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury.
23. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

24. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in.
25. The known producers/exporters in the subject countries, their Governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

Time Limit

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

30. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
31. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
32. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

38. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

39. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority